PK-SC/12.00/1N

(MR. CHAIRMAN in the Chair)

Q. No. 16

MR. CHAIRMAN: Question No. 16, hon. Member not present. Are there any supplementaries?

SHRI RIPUN BORA: Sir, I want to know from the hon. Minister about the procedure of refunding of railway ticket. When I have a confirmed ticket and after that the train is suddenly cancelled, what is the procedure to get the refund of my ticket/fare?

SHRI SURESH PRABHU: Sir, this question relates to online booking staff. So, I would request him that I can answer supplementaries related to this question.

MR. CHAIRMAN: Yes. ...(Interruptions)..

SHRI RIPUN BORA: No, no. ...(Interruptions).. This is related to this question. ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Do you have a supplementary on this question? ..(Interruptions)..

SHRI RIPUN BORA: Yes, Sir. This is related to this only. This is about e-ticketing. This question is regarding online ticketing. It is the same.

Q. No. 16 (CONTD.)

Yesterday they talked about so many reforms. But when I go for taking refund of my money, I have to run from pillar to post.

MR. CHAIRMAN: Ask a question. That's all.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I will read the question again if you permit me. It says, "(a) Whether it is a fact that railway pass holders do not have the facility to book tickets online...." This is something to do with them. Of course, I appreciate. There is a proper system for getting refund, which, if you want, I will send to you separately. I am not saying that this question is not relevant or.....

SHRI RIPUN BORA: No, no. The money is not refunded instantly. ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI RIPUN BORA: Money is not refunded instantly. ...(Interruptions).. You have to fulfil a lot of formalities to get back your money.

SHRI SURESH PRABHU: We will e-mail you the exact system. If you want, I will write a personal letter and send it to you. ...(Interruptions)..

श्री राम नाथ ठाकुर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेलवे पासधारकों के पास किसी भी पोर्टल द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक कराने की

Q. No. 16 (CONTD.)

सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सुविधा कब से शुरू की जाएगी?

श्री सुरेश प्रभु : सर, यह सुविधा, रेलवे में काम करने वाले लोगों को और रेलवे से रिटायर होने के बाद ऐसे 13-14 लाख लोग हैं, जिन्हें मिलती है। ऐसे सभी लोगों की सुविधा के लिए काफी सालों से कुछ नियमावली बनायी गयी है। इसका एक बिन्दु यह भी है कि जो nearest route है, आपको उससे जाना होगा, ताकि कुछ लोग ऐसा न करें कि यहां से असम जाना है तो पहले तमिलनाडु जाएं, फिर और कहीं जाएं और उसके बाद असम पहुंचें। इस तरह से वे न कर पाएं, इसके लिए यह नियम बनाया गया है। यह बिल्कुल सही है कि आज के ज़माने में इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूरा database है कि किसकी entitlement है। वह entitlement बेसिक पे के आधार पर होती है। जो ग्रुप "ए" और "बी" के ऑफिसर्स हैं, उनकी संख्या 16,360 है और ग्रुप "सी" और "डी" का जो स्टाफ है, उनकी संख्या 13,12,449 है। जो पास दिए जाते हैं, उनकी जो entitlement है, वह basic pay के आधार पर तय की जाती है और basic pay में बदलाव आ जाता है। इसलिए उसके लिए Human Resource Management (HRM) पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। हम लोग यह भी काम कर रहे हैं कि Enterprise Resource Planning की सुविधा से सारा database पूरी तरह से उपलब्ध हो, क्योंकि उसके बाद जब ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी तो उसका पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। इस सुविधा को देने के लिए जो backbone बनाने की जरूरत है, उस

Q. No. 16 (CONTD.)

पर काम चल रहा है। यह काम पूरा होने के बाद हम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दे पाएंगे।

श्री अजय संचेती : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने जवाब दिया है, मेरा सवाल उसी तरीके का था। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि यात्री कोई भी हो - चाहे पासधारक हो या पैसा देकर टिकट ले रहा हो, ऑनलाइन सुविधा दोनों को समान रूप से मिलनी चाहिए, उसके पे पैकेज से इसको लिंक करने का क्या उपयोग है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बिना किसी issue के, be it HR issues or all that, it should be directly linked, irrespective of any delay in the matter. This is my question. Can it be possible or not? Thank you, Sir.

(Followed by PB/1O)

PB-GS/1O/12.05

श्री सुरेश प्रभु: सर, सम्मानित सदस्य ने दो चीजों के बारे में बात कही है। जो मूल प्रश्न है, वह रेल में जो एम्पलॉईज़ होते हैं, उनको जो पास मिलता है, उसके बारे में है। आप जो बात कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही बात है। जो सीज़न टिकट होल्डर्स हैं, जो मुम्बई में, चेन्नई में, कोलकाता में या ऐसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, वहां पर suburban railway चलती है, तो वहां के जो लोग हैं, उनके लिए ज्यादा सुविधाएं कैसे दी जाएं।

Q. No. 16 (CONTD.)

सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंथली सीज़न टिकट है और क्वार्टरली टिकट है, उसको लोग चार तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा - across the counter कर सकते हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन से भी कर सकते हैं। आजकल ये सुविधाएं हमने शुरू की हैं और मैंने इसका inauguration भी किया था। आप जो बात कह रहे थे, उसको माननीय सदस्य ने भी पूछा - एक क्वेश्चन है कि आज जो pass facilities हैं, जो present employees और retired employees को दी जाती है, उसके बारे में कह रहे थे कि HRM system लाने की जरूरत है। आज आम आदमी जाना चाह रहा है, उसको यदि सीज़न टिकट बुक करना है, तो उसके लिए चार सुविधाएं हैं। मोबाइल ऐप से भी टिकट लिया जा सकता है और उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि suburban railway में पैसेंजर्स ट्रेवलिंग में 2015-16 में 446 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया है। उसमें से 50 करोड़ लोगों का रिजर्व टिकट है और आज 70 परसेंट ऑफ suburban railway...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair. ..(Interruptions)... I would request both Members and Ministers to address the Chair rather than each other. Question No. 17

(Ends)

Q.NO.17

SHRI D. RAJA: Sir, the issue raised is a very serious one. But the answer which has been given is very casual. Sir, the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited is a public sector drug company, HAL is a public sector drug company, IDPL is a public sector company. Why should these public sector drug companies be privatized? The answer says, it is done at the advice of NITI Aayog. Sir, NITI Aayog people say, it is "National Institute for Transforming India". Actually, it is acting as 'national institute for transferring public assets to private sector'. ...(Interruptions)...

Sir, public health must be the priority of the Government. Sir, you understand it. People do not have equitable access to healthcare. People are becoming poorer by spending more on healthcare and medical services. Instead of providing affordable drugs to people as the prices of medicines are going up, the public sector companies are being privatized.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI D. RAJA: My question is, why can't the Government think of modernizing these industries and increasing the production of drugs and providing it to the people at affordable price?

MR. CHAIRMAN: Thank you.

Q. No. 17 (CONTD.)

SHRI D. RAJA: Why can't the Government think of modernizing the industries?

MR. CHAIRMAN: Let your question be answered.

श्री मनसुख एल. मांडविया: सर, बीसीपीएल और एचएएल दो सार्वजनिक कम्पनियां हैं और ये फार्मास्यूटिकल कम्पनियां हैं। नीति आयोग ने सिफारिश की है और उसमें कुल मिलाकर 74 पीएसयूज़ हैं। जो 74 पीएसयूज़ सिक हुए हैं, सिक पीएसयूज़ का रिवाइवल करने के लिए भूतकाल में कोशिश की गई थी और वह कोशिश सफल नहीं रही। उसको बार-बार इंसेंटिव दिया गया था, लेकिन जब सफल नहीं रही, तब नीति आयोग ने निर्णय किया कि जो सिक कम्पनीज़ हैं, जैसे कि 74 ऐसे पीएसयूज़ हैं, उनको बंद करें या स्ट्रेटिजिक सेल करें, उसके संदर्भ में बीसीपीएल और हिन्दुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड इन दोनों कम्पनियों की स्ट्रेटिजिक सेल करने के लिए नीति आयोग ने जो सिफारिश की है और मंत्रिमंडल की एक कमेटी ने इस सिफारिश को स्वीकार करके केबिनेट ने निर्णय लिया है कि इन दोनों कम्पनियों का स्ट्रेटिजिक सेल किया जाए।

सर, यहां जो बात कही गई कि कम्पनी का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था, क्योंकि देश की आजादी के बाद फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हुई थी और जनता को essential medicines कम रेट पर मिलें, उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी और बाद में समय बदलता रहा।

(MCM/1P पर जारी)

SKC-MCM/1P/12.10

Q. No. 17 (CONTD.)

श्री मनसुख एल0 मांडविया (क्रमागत) : और नम्बर ऑफ कम्पनीज़ मार्केट में हैं और समय-समय पर उसके कम्पीटीशन में हमारी गवर्नमेंट कम्पनी ठीक नहीं रही है, इसलिए वह घाटे में चली जा रही है। घाटे को फुलफिल करने के लिए सरकार ने दो बार, तीन बार कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। जनता को affordable medicines मिलें, उसके लिए हमारी सरकार का कमिटमेंट है और इसलिए एन0पी0पी0ए0 के माध्यम से आज हमने 700 से अधिक medicines का सैलिंग प्राइस फिक्स कर दिया है और प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र के माध्यम से आज सारे देश में a number of medical stores ओपन करके, वहां 50 परसेंट से कम रेट में हम medicines उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए निर्णय किया गया।

SHRI D. RAJA: Sir, I don't agree with this answer. In fact, the Government is deliberately making public sector units sick and putting them up on strategic sale. Having said this, I would like to put this question through you, Sir: In 2013, the Parliamentary Standing Committee on Commerce, headed by Shri Shanta Kumar, had recommended "...so as to make available an adequate supply of generic essential medicines for public health services". The logic given by the Committee was that "...this had become necessary as private companies were not the answer to the need for

Q. No. 17 (CONTD.)

adequate supply of essential affordable generics." The Committee also said that the sick units must be revived. What efforts did the Government make? It is a Parliamentary Standing Committee's Report. Have you given any respect to the recommendations made by the Parliamentary Standing Committee? Instead of reviving the sick public sector units, you make them further sick and try to sell them. What do you want to do in this country? The public sector is being broken and destroyed in this manner. It is the strength of our economy, the strength of our system.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Let it be answered.

श्री मनसुख एल0 मांडविया : सर, यह जो सार्वजनिक कम्पनी है, हमारे समय में सिक नहीं हुई है। जो एच0ए0एल0 है, वह 1992 में सिक हुई, जो बी0सी0पी0एल0 है, वह 1976 से सिक होती आई है और 1977 में इसको भारत सरकार को हैंडओवर किया गया था। सर, विषय यह है कि जो कम्पनी पुराने समय में सिक हुई है, पुराने समय में सिक होने के बाद जब उसकी liability बढ़ती रही, तो सरकार ने बार-बार कोशिश भी की। सर, सरकार ने दो बार 1992-1993 और 1997 में IDPL, HAL और BCPL को डॉयरेक्ट मदद भी की, लेकिन ये कम्पनीज़ सस्टेन नहीं हुई हैं, ये कम्पनीज़ प्रॉफिट में नहीं आईं और उनकी liability बढ़ती रही। वैसी स्थिति में सरकार ने कोई न कोई उपाय करना चाहिए था। बाद में नीति आयोग की एक समिति गठित हुई। नीति आयोग ने सिफारिश

Q. No. 17 (CONTD.)

की और उसके साथ-साथ जो फार्मा कम्पनी है, हमारा कमिटमेंट जनता को है कि एफॉर्डेबल मेडिसिन्स मिलें, उसके लिए वह कायम रहा है और उसके लिए हमने अनेक उपाय किए। उसमें से ही प्रधान मंत्री जनऔषधि योजना के माध्यम से ऐसी medicines हैं, जो 700 से अधिक medicines हैं और 150 से अधिक मेडिकल डिवाइसेज़ हैं। ये medicines और मेडिकल डिवाइसेज़ 50 परसेंट से कम रेट पर हैं। डायबिटीज़ की medicine है, जिसकी एक स्ट्रिप का प्राइस 10 रुपए है। तो प्रधान मंत्री जनऔषधि केन्द्र पर जाएंगे तो उसको मेक्सिमम 5 रुपए, तीन रुपए, दो रुपए में मिल सकती है। यह हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी का जनता के प्रति कमिटमेंट है कि देश का कोई गरीब दवा के बिना नहीं मरना चाहिए। उस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Anand Sharma.

SHRI D. RAJA: Sir, what kind of an answer is this? We are asking about public sector drug companies and he is talking about the Pradhan Mantri Yojana! I am asking about public sector drug companies. Why are you making them sick and then putting them up on sale? ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Sharma *saab*. ...(Interruptions)..

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the Minister's answer is not satisfactory. Pharmaceutical is an important national subject, particularly the production of life-saving medicines and their availability. There have been concerns

Q. No. 17 (CONTD.)

over the years that efforts were being made to acquire Indian pharmaceutical production capacities by entities, not in this country, but foreign entities. Therefore, a conscious view was taken by the earlier Government that when it comes to FDI and when it comes to acquisition of critical pharmaceuticals, like those for oncology, injections and vaccines, we will not allow more than 26 per cent FDI so as to protect national capabilities and assets.

(CONTD. BY HK/1Q)

HK-HMS/12.15/1Q/

SHRI ANAND SHARMA (CONTD.): At the same time, FIPB will scrutinize any attempt where FDI or investment coming from foreign shores is more than the threshold which may threaten India's own production capacities. Now, Sir, two things have happened. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am linking it to the question. Since we have done away with that scrutiny, since we have done away with the ground field acquisitions and now we have done away with the FIPB itself, what guarantee is there that our critical pharmaceutical units, particularly in the

Q. No. 17 (CONTD.)

Public Sector Undertakings, in the name of strategic sales will not be sold over to foreign entities to create monopolies which will hurt India's own capacity for production of essential medicines?

श्री मनसुख एल0 मांडविया : सर, पहली बात तो यह है कि किसी विदेशी कंपनी को भारतीय फार्मा कंपनी बेचने का आयोजन नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वर्ष 2005 में एक Rehabilitation plan बनाया गया, उस समय स्थिति यह हुई कि यह वर्ष 2005 में बना और 2007 में उसका implementation हुआ। उस बीच में liability बढ़ी और वैसे ही liability बढ़ती चली गयी। महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है कि उसका effect देश में strategical pharma production पर होगा, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि as on today, situation is that कि देश में 1 लाख करोड़ का हमारा domestic market है और 1 लाख करोड़ का international market है। कुल मिलाकर फार्मा इंडस्ट्रीज का व्यापार 2 लाख करोड़ का है, जिन में से सिर्फ 65000 domestic companies का शेयर कम रह गया है, इसलिए गवर्नमेंट पीएसयूज के बंद होने से देश में आम जनता को essential medicines मिलने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

श्री नारायण लाल पंचारिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके विभाग में कितनी ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो घाटे में

Q. No. 17 (CONTD.)

चल रही हैं और घाटे में चलने वाली उन कंपनियों में से कितनी कंपनियों को सरकार बंद करने जा रही है और कितनी कंपनियों को अप करने जा रही है?

श्री मनसुख एल0 मांडविया : सर, मेरे विभाग में हिंदुस्तान एंटी-बायोटिक्स लिमिटेड, आईडीपीएल, आरडीपीएल, बीसीपीएल और केएपीएल पांच सार्वजनिक कंपनियां हैं। उनमें से नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार हम एचएएल और बीसीपीएल को बंद नहीं करना चाहते हैं। दो कंपनियों की हम strategic sale करेंगे और उनके साथ-साथ के0ए0पी0एल0 जो हमारी profitable company है, उसकी strategic sale या बंद करने की आवश्यकता नहीं है। महोदय, आईडीपीएल और आरडीपीएल कंपनियों की liabilities भी बहुत बढ़ी हैं और उनका networth भी आज 7,147 और आरडीपीएल का (-) 24.65 है। महोदय, दोनों का माइनस networth होने से हमने ये दो कंपनियां क्लोज करने का निर्णय लिया है।

SHRI C.P. NARAYANAN: Sir, the hon. Minister has said that under the previous Government it was loss-making. Now what the Government is doing is that they collect medicines and sell it through *Pradhan Mantri Janaushadhi Pariyojana*. Is it 'Make in India'? It is wholesale agency. Is our present Government's policy to run a wholesale agency or 'Make in India' project which means producing? If the Government is producing, how many essential drugs are being produced by the Public Sector companies? Why

Q. No. 17 (CONTD.)

are these two companies being sold? The Government, as far as I know, can design technology through various institutions for developing new methods of producing medicine. Why are we not making use of those things?

(Contd. By 1R/GSP)

ASC-GSP/12.20/1R

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, हम 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से फॉर्मास्यूटिकल्स सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश में फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ 10 per cent ग्रोथ से आगे बढ़ रही हैं। पूरे देश में GST बिल लागू होने से इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश में अभी ऐसी स्थिति थी कि सभी स्टेट्स में अपना-अपना टैक्स होता था और आज कोई स्टेट टैक्स होलिडे डिक्लेयर करती थी, तो उस स्टेट में फॉर्मास्यूटिकल कम्पनी उसका लाभ लेने के लिए चली जाती थी। GST लागू होने से एक समान कर develop होगा और फॉर्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ को और बल मिलेगा। इसके साथ-साथ जो भी संभव था और जो संभव है, हम उसको भी जारी रखना चाहते हैं। जो प्रॉफिटेबल कम्पनी KEPL है, वह कैसे आगे बढ़े? जिन कम्पनीज़ का नेटवर्क माइन्स में ज्यादा चला गया है तथा उसके रिवाइवल की संभावना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में ही हम उनको क्लोज़ कर रहे हैं तथा IDPL व RDPL इन दो कम्पनीज़ को ही

Q. No. 17 (CONTD.)

क्लोज़ कर रहे हैं तथा दूसरी कम्पनीज़ की स्ट्रेटेजिक सेल करेंगे और जो प्रॉफिटेबल कम्पनीज़ हैं, हम उनको चालू रखेंगे।

(समाप्त)

Q.No. 18

MR. CHAIRMAN: Question No. 18. Questioner not present. Let the answer be given. Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Government has decided to sell the surplus land of IDPL, RDPL and BCPL. Sir, I think, NITI Aayog suggests nothing but the sale of the lands of public sector undertakings. Sir, instead of reviving the sick units and studying the reasons as to why they have fallen sick, the Government is in a hasty move to close down all the public sector undertakings.

Sir, the public sector undertakings are the temples of economy of our country. When the whole world faced economic recession, India withstood the same only because of these PSUs. Sir, I was the Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Industry. The Committee's study revealed that the reasons of sickening of the PSUs are mainly mismanagement and non-upgradation of technology. So, instead of concentrating on that side, why is the Government in haste to shut down these PSUs? There should be a coordination between the DPE and the concerned Ministries, which should safeguard these PSUs as well as the employees. Non-revision of pay of employees also results in low morale.

Q. No. 18 (CONTD.)

So, I think, the Government has to concentrate more on revival and resilience of the public sector undertakings. It should then take all such steps which they have to take, instead of accepting all the suggestions given by the NITI Aayog.

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमें किसी भी गवर्नमेंट PSUs के बेचने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे PSUs हैं, जिनका रिवाइवल करना मुश्किल है, जिनके रिवाइवल करने में दिक्कतें हैं, ऐसी PSUs के बारे में हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। उनके ऊपर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। नीति आयोग ने जो सिफारिश की है, उस सिफारिश के ऊपर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने विस्तार से डिस्कशन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने डिस्कशन करने बाद ही केबिनेट को रिकमेंड किया है। ऐसी कम्पनीज़ के लिए ही रेकमेंडेशन किया गया है, जिनका सर्वाइवल करना मुश्किल है, हम ऐसी ही PSUs को क्लोज़ करेंगे। जिन PSUs में यदि थोड़ी भी संभावना है, तो हम ऐसी PSUs की स्ट्रेटेजिक सेल से भागीदारी बनाए रखने के बाद ही उसके साथ काम करेंगे। हमने वहां काम करने वाले कर्मचारियों तथा उनके हितों के बारे में भी विस्तार से विचार किया है। हमारे मंत्रालय ने भी यह विचार किया है कि जब उसकी स्ट्रेटेजिक सेल हो या वह क्लोज हो, तो उसके employees की जो liabilities हैं, उनका ध्यान रखा जाए। उनको नियमों के अनुसार VRS दिया जाए। जिसकी भी स्ट्रेटेजिक सेल होगी, ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी VRS

Q. No. 18 (CONTD.)

लेना चाहेगा, उसको VRS दिया जाएगा तथा कम्पनी की balance sheet को clear किया जाए। जो भी कर्मचारी जॉब करना चाहते हैं, तो नीति आयोग और प्राइवेट एन्टरप्राइजेज़ मिनिस्ट्री की जो कमेटी है, वह उनके बारे में विचार करेगी। जो भी वहीं पर जॉब करना चाहेंगे, तो उनको तीन साल तक के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए और उसको सर्वाइव किया जाए, हम यह भी ध्यान रखेंगे।

SHRI D. RAJA: Sir, what is the mandate of the NITI Aayog?

MR. CHAIRMAN: Your question is finished. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, please allow him. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...(Interruptions)...

(followed by YSR/1S)

-GSP/YSR-KLG/12.25/1S

SHRI D. RAJA: Sir, what is the mandate of NITI Aayog? ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we seek your protection. The Minister's answer has raised a larger issue, which is about the strategic sale of PSUs and NITI Aayog's role.

MR. CHAIRMAN: That is a subject for separate discussion.

SHRI ANAND SHARMA: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Give notice for a discussion on it.

Q. No. 18 (CONTD.)

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it raised an issue on the mandate of NITI Aayog. It is nebulous. Nobody knows about it. Is the NITI Aayog going to decide a grand clearance sale of Public Sector Undertakings?

MR. CHAIRMAN: That is a subject for separate discussion.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is the right of the House to know now...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, no. Give notice for a discussion.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we seek your protection. Let the Prime Minister or the Finance Minister come and inform the House.

MR. CHAIRMAN: Fair enough.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, you give a direction. ...(Interruptions)... Not today, but in this Session, let them come and make a statement. ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Let this matter be discussed through appropriate procedure.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we are only requesting...(Interruptions)... The Chair has the authority to direct the Government to make a statement.

Q. No. 18 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: I am suggesting a way out. Let this matter be a subject of a separate discussion.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we will do that.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, it is becoming very clear that the intent of the present Government is to locate the surplus land of the sick units and sell it as per their advantage. The duty of the IDPL, RDPL and BCPL is to just look for the surplus land. I would like to mention one important point here. The Ministry of Ayush is in search of Government land to start production units. I would like to know whether the Ministry would consider giving the surplus land to the Ministry of Ayush to expand its production.

श्री मनसुख एल. मांडविया: सभापति महोदय, हमारे जो सिक यूनिट्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए यह लैंड की बिक्री की बात हुई है। इसमें जो उस यूनिट की बेलेन्स शीट है, उसको ठीक करने के लिए जितनी आवश्यकता होगी, उतनी ही लैंड हम सेल करेंगे और वह लैंड भी कंपीटीटिव बिडिंग से ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let it be answered.

श्री मनसुख एल. मांडविया: सर, वह लैंड भी हम कंपीटीटिव बिडिंग से गवर्नमेंट एजेन्सीज़ को सेल करेंगे, किसी प्राइवेट व्यक्ति को हम देने वाले नहीं हैं। हम उसको

Q. No. 18 (CONTD.)

पारदर्शिता से सेल करेंगे और उतनी ही लैंड को सेल करेंगे, जिससे हमारे इंप्लॉईज़ और कंपनी की सारी लाइबिलिटीज़ खत्म हों। उतनी ही हम सेल करेंगे।

श्री लाल सिंह वडोदिया: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने जब देश की प्रजा को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, तो ऐसे समय में दवाइयां बनाने और उनकी प्रोग्रस के लिए यह जमीन बेचने के बजाय भविष्य में इनके डवलपमेंट के लिए रिजर्व रखी जाए, क्या ऐसा कुछ सरकार कर सकती है?

श्री मनसुख एल. मांडविया: माननीय सभापति जी, ज्यादा जमीन बेचने का हमने कोई विषय नहीं रखा है। हम उतनी ही लैंड को सेल कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सिक यूनिट जो क्लोज हो रहे हैं और यह स्ट्रेटिजिक सेल करना है, जिससे यूनिट की सभी लाइबिलिटीज़ खत्म हों, पूर्ण हों। उतनी लैंड हम सेल करेंगे, बाकी की लैंड सरकार के पास ही रहेगी, कंपनी के पास ही रहेगी, ताकि आवश्यकता के अनुसार सरकार जो नीति बनाएगी, उसके अनुसार उसका उपयोग हो सकता है।

(समाप्त)

Q.No.19

MR. CHAIRMAN: Question No. 19. The questioner is not present. Let the answer be given.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, the growing requirement of cashless transactions has thrown a challenge to have skilled repairers of ATMs. I would like to know from the Union Ministry whether it is going to give any credence to the industrial institutes where class eight or class ten passed students are getting trained to repair hardware and electronic equipment. With the involvement of the Ministry of Electronics and Information Technology, the ITIs can attain the status of service providing and technology expanding institutions.

(Contd. by VKK/1T)

-YSR/VKK-AKG/1T/12.30

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (CONTD.): Are you contemplating to give any extra focus to give support to the ITIs in the country?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am happy to inform the hon. Member about this. His question is a very valid question. Indian IT sector has done great service to the country. Indian IT industry today is present in 200 cities of 86 countries and, Sir, the revenue rollover in 2015-16, the House needs to

Q. No. 19 (CONTD.)

know, has been Rs.8,40,000 crore and the export has been at all-time high of Rs.7,00,000 crore. Sir, they employ 37 lakh professionals directly and one crore indirectly. In the last two years, we have given jobs to two lakh people; out of which, more than one-third are women.

MR. CHAIRMAN: Could you respond to his suggestion?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Now, as far as the skilling part is concerned, apart from NIELIT and C-DAC, which are giving professional skilling courses, we are also taking up a big skilling course, including non-Government, Government, smaller bodies, which can be involved in skilling in IT products. One thing more I would like to inform the hon. Member that of late, electronic manufacturing is becoming a very big activity in India. We have received proposal of Rs.1,26,000 crore and India is becoming a big hub of mobile manufacturing. Sir, I am very grateful to inform the House that in the last one-and-a-half years, 72 mobile manufacturing units have come in India – 42 mobile and 30 component manufacturing factories – in a very big way giving job to nearly two lakh people directly and indirectly. All this surely will lead to higher skill. Sir, we have a good number of IITs, NITs, IIITs and so many ITIs. All have to work together for the enhancement of the skilling

Q. No. 19 (CONTD.)

potential of India and the Government of India is encouraging all this in a very, very purposive way.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: They are yet to be connected with the IITs, NITs and all.

MR. CHAIRMAN: Please, your question is over. Now, Shrimati Kahkashan Perween.

श्रीमती कहकशां परवीन : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रति वर्ष 5 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अनुसार 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के हिसाब से लगभग 15 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि प्रशिक्षित व्यक्तियों को कहीं नौकरी मिली या नहीं, क्या इसका कोई डेटा इनके पास है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि इन्होंने दो सालों में किस राज्य में कितने लोगों को इन कामों में प्रशिक्षित किया है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैं माननीय सदस्य महोदया को बहुत विनम्रता से बताना चाहूँगा कि अगर वे मेरे इस उत्तर के Annexure को विस्तार से पढ़ेंगी, तो NIELIT ने 4 लाख लोगों को train किया है, C-DAC ने 5 हजार लोगों को train किया है और 1,500 को हम PhD दे रहे हैं। अगर आप इसके Annexure के III को देखें, तो 2,29,700 candidates Skill Development में enrol हुए, जिनमें 1,81,316 train हो चुके हैं। अब

Q. No. 19 (CONTD.)

यह प्रदेशवार कितना है, मैं आपको इसकी सूची भेज दूँगा। एक बात अवश्य है कि Digital India की व्यापकता में प्रदेश और केन्द्र, दोनों को साथ-साथ मिल कर चलना है। इस दिशा में राज्यों को जो भी सहयोग चाहिए, वह हम अवश्य देंगे।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 20

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्टेशनों पर जनता के आवागमन की सुविधाओं के बारे में विस्तार से क्या काम किया जा रहा है तथा उनमें उज्जैन, रतलाम, इन्दौर, भोपाल, इटारसी, नागपुर, जयपुर और कोटा के कुछ स्टेशंस का नाम देकर उनके बारे में कहा है। मुझे खुशी है कि माननीय रेल मंत्री जी ने अपने इस उत्तर में इसका हवाला दिया है कि वे कहाँ escalator स्थापित कर रहे हैं और कहाँ लिफ्ट लगा रहे हैं। वैसे भी मैं रेल मंत्री जी को नए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उनके अन्तर्गत इन सारी योजनाओं को पूरा करने की संभावना को देखते हुए बधाई देता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आदर्श स्टेशंस के अन्तर्गत जो स्टेशंस लिए गए हैं, वहाँ इस अवधारणा, इस concept को पूरा करने में कितना समय लगेगा और इसके लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?

(1यू/एससीएच पर आगे)

-VKK/SCH-BHS/12.35/1U

श्री सुरेश प्रभु : सर, यह सही है कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रखने की कोशिश की है, खास तौर पर बुज़ुर्गों और दिव्यांगों को जो दिक्कतें आती हैं, उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं देने का प्रबंध शुरू किया है। उनके लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स की सुविधा दी जाएगी, जो स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ा और अहम काम है। हम लोगों ने 770 एस्केलेटर्स लगाने की योजना बनाई है और जल्दी ही उनको लगाए जाने की शुरुआत की जाएगी।

Q. No. 20 (CONTD.)

जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, यह बात बिल्कुल सही है कि सभी स्टेशनों में लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन शुरू में 'ए-वन' कैटेगरी, 'ए' कैटेगरी और 'सी' कैटेगरी के स्टेशंस के ऊपर ज्यादा जोर देकर हम लोगों ने काम की शुरुआत की है। शायद आपको मालूम होगा कि 75 स्टेशंस 'ए-वन' कैटेगरी में आते हैं, 302 स्टेशंस 'ए' कैटेगरी में आते हैं और 483 स्टेशंस 'सी' कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ इनमें से कुछ स्टेशंस को आदर्श स्टेशंस की कैटेगरी में भी चुना गया है, आपने इसके संबंध में पूछा भी है। सभी आदर्श स्टेशंस पर अभी ये सुविधाएं देने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो धन लगता है, वह passenger amenities के अंतर्गत आता है। पिछले कुछ समय से ही हमने passenger amenities को बढ़ाने की शुरुआत की है। इसके लिए पिछले तीन साल से करीब 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया जा चुका है। हमें यह भी पता है कि यह धन भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों की मांग ज्यादा है, इसलिए इसको देखते हुए हमने CSR के तहत भी कुछ कंपनियों से अपील की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि कुछ कंपनियों ने आगे आकर इस काम के लिए हमें बहुत बड़ी मदद भी की है, जैसे WCL ने हम लोगों को 30 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे हम लोग कैटेगरी 'सी' के स्टेशंस में भी इस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक यह अपील करूंगा, जैसे कि कुछ सांसदों ने ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Just answer his question.

Q. No. 20 (CONTD.)

SHRI SURESH PRABHU: His question was: How soon will I be able to fulfil it? I am saying, it depends upon the availability of resources. That is why passenger amenities have been stepped up. We are getting CSR funds. There are a lot of hon. Members who have given Rs.5 crores each from their contribution. So, if you can also contribute, I will be very happy to do it.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, second question.

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, बात यह है कि जो मॉडल स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, उन मॉडल स्टेशंस के काम को पूरा करने के लिए हमें कोई न कोई लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा। हम पुराने स्टेशंस में छोटे-बड़े बदलाव करके, वहां कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, केवल इससे तो ये बातें पूरी नहीं होंगी। नए प्रकार से उसकी रचना करके इस काम को करना होगा।

महोदय, नागदा का जो स्टेशन है, वह बड़े औद्योगिक क्षेत्र में आता है। उसके दोनों छोरों पर, एक तरफ इंडस्ट्री है और दूसरी तरफ शहर बसा हुआ है, इसलिए उन दोनों छोरों पर सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता है। नागदा जंक्शन एक एक बड़ा स्टेशन है।

स्वच्छता अभियान के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यह स्वच्छता अभियान हमारे लिए सभ्य समाज की ...(व्यवधान)...

Q. No. 20 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Please ask your question.

डा. सत्यनारायण जटिया : मेरा क्वेश्चन सीधा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्टेशंस को साफ-सुथरा रखने एवं अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या आपने अभी तक कोई कार्यक्रम बनाया है? यदि बनाया है, तो आप उसकी कार्य योजना को कैसे पूरा करेंगे? आज भी स्टेशंस पर बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, जिनको दूर किए जाने की जरूरत है।

MR. CHAIRMAN: That is a specific question. It can be answered specifically.

श्री सुरेश प्रभु : सर, इन्होंने दो बिन्दुओं पर अपना प्रश्न पूछा है। एक तरह से इसमें हम लोग incremental हैं। जिन स्टेशंस पर कोई सुविधा नहीं थी, वहां सुविधाएं देने की शुरुआत की गई है, लेकिन साथ-साथ स्टेशन को पूरी मात्रा में redevelop करने का कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। कुछ स्टेशंस पर काम शुरू कर दिया गया है और बाकी के स्टेशंस में भी आने वाले कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। कई स्टेशंस के लिए on bidding इस काम को शुरू किया गया है, ये स्टेशंस airport से भी ज्यादा अच्छे होंगे। इस तरह हम लोगों ने bidding करवाने के काम की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि जिन सुविधाओं की बात आप कह रहे हैं, all stations will be fitted with all modern amenities.

Q. No. 20 (CONTD.)

स्वच्छ रेलवे का जो अभियान है, उसके तहत बहुत सारे बिन्दु आते हैं। पिछले दो सालों में 25,000 बॉयो-टॉयलेट्स लगाए गए हैं और इस वर्ष के लिए हमारा टार्गेट 30,000 बॉयो-टॉयलेट्स बनाने का है। इसके साथ ही ऑन-बोर्ड क्लीनिंग की सुविधा की भी शुरुआत भी की गई है। 780 गाड़ियों में closed loop 'App' द्वारा इसकी निगरानी रखी जा रही है। हर रोज़ 1 लाख लोगों से online passenger feedback लिए जा रहे हैं, while they are still travelling. Third-party feedback भी लिए जा रहा है, अभी तक 1.3 लाख लोगों से ये लिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त mechanised cleaning equipments लगाए जा रहे हैं, additional toilets लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी से cleaning monitor करने की शुरुआत भी हमने की है। इस तरह कुछ और भी बिन्दु हैं, जिनके ऊपर मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक लोगों के सहयोग से हम और ज्यादा काम कर पाएंगे।

DR. NARENDRA JADHAV: The hon. Minister's response is very comprehensive and informative. It talks about improvement in railway stations, bridges, lifts, even CCTVs, and cleanliness etc.

(Contd. by DC/1W)

DC-RPM/12.40/1W

Q. No. 20 (CONTD.)

DR. NARENDRA JADHAV (CONTD.): Regrettably, however, the response does not say anything about making the railway stations physically disabled-friendly, *divyang*-friendly. Mr. Chairman, Sir, Suburban Railway travel in cities like Mumbai, is generally a torture. Mr. Sachin Tendulkar, who is here, will bear me out but, for physically disabled, it is nothing but a nightmare. Sir, I would like to raise a supplementary question. What are the provisions which the Government is coming up with to make the railway stations disabled- friendly? Is there a target date by which the projects are going to be completed? Is there a time-bound programme? Sir, I will take only 30 seconds. This is a low-cost improvement which will go a long way in alleviating the extreme difficulties currently faced by the disabled, *divyangs*, as well as senior citizens.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I fully share the compassion and the concern of the hon. Member. It is absolutely relevant to know that we are working on this very important issue. This is absolutely right that most of the stations, till recent past, were not disabled-friendly, inaccessible to many people and, therefore, to make all stations *divyang*-friendly is our objective, but it will

Q. No. 20 (CONTD.)

begin in small steps. All new stations and all new coaches which are getting constructed will be *divyang*-friendly. We have already set the target. I will not be able to give the number just now because right now this is under trial. I will definitely share it with you. But the whole idea is, all the major stations, wherever there is a need for it, we are trying to make them *divyang*- friendly. All new stations are planned like that and all new coaches are already planned as *divyang*-friendly coaches. And, in fact, we have invited some experts in this field to understand as to how the design should be and, therefore, we are really working on it.

श्री माजीद मेमन : माननीय सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी से अभी हमारे एक मित्र ने मुम्बई के बारे में पूछा। बदकिस्मती से रेल का बजट अलग से नहीं रखा गया, नहीं तो विस्तार से हम कई सवाल उनसे पूछ सकते थे, लेकिन चूंकि अब मौका है, इसलिए मैं इस प्रश्न से जुड़े हुए विषय के बारे में माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और वे इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि मुम्बई शहर की लोकल ट्रेनों की परिस्थिति, जिसके बारे में अभी हमारे मित्र श्री नरेन्द्र यादव जी ने कहा, वह ऐसी है कि अगर कोई लोकल ट्रेन 30 या 45 सेकंड भी लेट हो जाती है, तो पीक टाइम में ऐसी अवस्था होती है कि प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स को खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है।

Q. No. 20 (CONTD.)

महोदय, जहां तक एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स के प्रावधान की बात है, मुझे लगता है कि मुम्बई में ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर या तो लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रोविज़न होना चाहिए। Disabled commuters, elderly commuters, women and sick commuters are finding it very difficult to climb from one platform to another when the announcements are made that the train is coming say on platform no. 5 instead of platform no. 3. सर, यह बहुत आवश्यक है। मैं रेल मंत्री जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष में जनरल मैनेजर्स सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की, खासदारों यानी सांसदों के साथ मीटिंग रखी थी। मगर उसके फलस्वरूप कुछ हो नहीं पाया। आपका अलग बजट नहीं आया। हमारी बड़ी आशाएं थीं कि आप मुम्बई के लिए बहुत कुछ देंगे, ताकि मुम्बई के कम्यूटर्स को सुविधाएं मिलें।

श्री सुरेश प्रभुः सर, हमारे सम्माननीय सदस्य बहुत जाने-माने एडवोकेट हैं। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुम्बई के लोगों की समस्या हमारे सामने रखी है और उन्हें जानकर खुशी होगी कि देश के इतिहास में शायद पहली बार एक शहर के लिए 55 हजार करोड़ रुपए की, अपग्रेडेशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में दिसम्बर, 2016 में यानी लगभग पांच हफ्ते पहले हम लोगों ने लॉंच की थी। उसमें एलीवेटेड कॉरीडोर भी है। उसमें हमारा मुम्बई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-तीन भी है और उसमें 55 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद, मुझे विश्वास

Q. No. 20 (CONTD.)

है कि लोगों की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। इस बारे में बजट में भी लिखा है। जब उन्हें बजट की पूरी जानकारी मिलेगी, तब वे इससे अवगत हो जाएंगे।

महोदय, मुम्बई में लिफ्ट्स लगाने के लिए, जैसा मैंने कहा, आपको सुनकर खुशी होगी कि हम लोगों ने 30 करोड़ रुपए सिर्फ सीएसआर के तहत डब्ल्यूसीएल से लिए हैं और उसमें 33 स्टेशन्स जिनमें अलग-अलग स्टेशन्स हैं, यानी सेंट्रल रेलवे के 19 स्टेशन्स हैं और वेस्टर्न रेलवे के 14 स्टेशन्स हैं, उनके ऊपर काम करने की शुरुआत हुई है। कुछ टेंडर्स भी इश्यू किए गए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भी लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि मुम्बई में जिस तरह से ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, वहां 75 लाख लोग रोज ट्रांसपोर्ट सबअर्बन सिस्टम का यूज करते हैं और उसमें पिछले 40-50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और इन्फ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। इसके लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(1एक्स/पीएसवी पर आगे)

PSV-KR/1X/12.45

श्रीमती विप्लव ठाकुर :माननीय सभापति जी ,मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगी कि दिल्ली स्टेशन पर आपने एस्केलेटर लगाया हुआ है ,जो फर्स्ट नम्बर प्लेटफॉर्म पर जाता है ,लेकिन उसके बाद प्लेटफॉर्म-2 ,प्लेटफॉर्म-3 ,प्लेटफॉर्म-4 या प्लेटफॉर्म-5 पर

Q. No. 20 (CONTD.)

लोगों को सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है। जो ओल्ड हैं ,सीनियर सिटिजंस हैं या जिस तरह से इन्होंने कहा हैंडिकैप्ड लोग हैं ,उनको वहाँ जाने के लिए अपना सामान उठाकर उन सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह जो आपका प्रोग्राम है, इसे आप पहले दिल्ली में क्यों नहीं शुरू करते ,जहाँ पर सारे भारत के, सारी दुनिया के लोग आते हैं और उन सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है? तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि उसके लिए ये क्या प्रावधान करने जा रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रभु :सर ,जैसा मैंने कहा कि सब जगहों पर A, A Plus and C category में हम लोग एस्केलेटर्स लगाने जा रहे हैं। जैसे नयी दिल्ली स्टेशन लीजिए ,यह बिल्कुल सही है कि उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यदि हम एक ही स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगाएँगे ,तो हमारे पास जो मर्यादित मात्रा में धन उपलब्ध है ,उससे शायद वह कुछ स्टेशंस पर ही लगेगा। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा स्टेशंस पर यह लगे। यदि हमें धन उपलब्ध होगा, ...(व्यवधान)... यह आप भी जानते हैं कि रेल की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है ,उसके बाद भी ,जैसा मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने उसमें बढ़ोतरी भी लाई है। यह बिल्कुल सही है कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर यह लगना चाहिए। मैं भी यह मानता हूँ ,लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि पिछले ढाई सालों में जितने एस्केलेटर्स

Q. No. 20 (CONTD.)

लगे हैं ,उनकी मात्रा अगर आप देखें ,तो ढाई साल पहले वे कितने थे और कितनी बड़ी मात्रा में लगे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए. ...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर :सर ,... ...(व्यवधान).....

(समाप्त)

Q.No. 21

MR. CHAIRMAN: Q.No.21. The questioner is not present. Let the answer be given.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Mr. Chairman, Sir, thank you very much. Sir, BSNL broad band users face problems from the domain main server. The DNS is not that much active. It doesn't respond many times because the new default router when we get a new BSNL connection usually they don't give us the better performance quality products. So, because of this, we usually face problems. At times, Sir, we have to pay four times more than the private players, which give us better connectivity than BSNL. I want to know from the hon. Minister whether the BSNL and MTNL internet service providers come up with the time and use the latest technology and upgrade their equipment so that the connectivity could be improved in the near future.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister, Shri Manoj Sinha is absent; and on his request you are kind enough to allow me to reply on his behalf.

Q.No. 21(CONTD.)

Sir, I have taken note of the suggestion of the hon. Member. BSNL is improving a lot of its operational activities and requirements. There has been a legacy issue to which I had occasion to earlier share in the House. It had a profit of Rs.10,000 crore in 2004. It came down to Rs.8,000 crore loss. But today I am happy to announce in this House that their operating profit has gone up by Rs.4,000 crore and the losses are also coming down. Their revenue also has gone up. You are right; they are investing in new products. There is greater need for involvement. They are giving one Mega-byte free services for the whole broad band. Surely, we take note of your suggestions. If any specific complaint is there, our official would respond to it.

Sir, one thing this House needs to know. It is very important. My good friend, Mr. Raja was talking about PSUs. The human resource component of BSNL/MTNL is 50 per cent of their revenue expenditure.

(Continued by 1Y/KS)

KS-VNK/1Y/12.50

Q.No. 21(CONTD.)

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Establishment cost!

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, in the case of the private sector, establishment cost is only two to three per cent. In spite of this heavy load, for good measure, we need to support employment. If they are doing so well, coming into profit, making new investment and turning things around, I think this initiative needs to be appreciated. Secondly, this House also needs to remember that during natural calamities, it is only these public bodies which provide free services. We need to appreciate that. We know that very well in the case of Chennai. So, the good part also needs to be appreciated. If there is any specific issue, we would certainly look into that.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Hon. Chairman, Sir, we are now in the age of 'struck-up India', 'hanging India' and 'hacking India'. I am aware of the capability and the comprehension of the senior Minister. Even though the regular Minister is absent, I would like to know from him what the Government's take on broadband connectivity is. What is the scope and necessity of broadband connectivity at present, keeping in mind the growing

Q.No. 21(CONTD.)

demand of cashless digital transactions in the light of demonetization, so as to serve the PIOs and aid such cashless transactions, which are increasingly leading to hanging of websites and struck-up credit card transactions? Keep this in view while assessing broadband connectivity and its future requirements.

SHRI ANAND SHARMA: It is the computers that are hanging, not human beings!

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I was also taken aback! I am grateful. Sir, I appreciate the interest shown by the hon. Member in digital payments. Keep it up!

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I also take a lot of interest in cyber.... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please; you have asked your question.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We would all be benefited by your wisdom one day.

Sir, as far as Internet penetration is concerned, his point is fairly well taken. India today is home to about 50 crore Internet penetrations. We need to increase it. We are expanding connectivity of *Gram Panchayats*

Q.No. 21(CONTD.)

through the Optical Fibre Network. I want to gently remind this House that it was started by your Government, Mr. Anand Sharma. It was known as NOFN. Now, we have made it *Bharat Net*. It was started in 2011. Till 2014, in three years, the total length of optical fibre laid was 358 kilometres. We have laid down 1,92,000 kilometres in two-and-a-half years. That is how we are doing it. We need to take it further. Private players too are coming in. Wireless (WiFi) technology is coming up in a very big way. All these are designed to make it more and more pro-people.

Sir, I go to a lot of these Startup convocations. I see young people doing so well and coming up with new technology for broadband. We all need to work together. I do take your suggestion on board, but let me tell you, Indians first observe technology, then adopt it and, finally, they become empowered in the process. I see a lot of new technologies coming up in India to further expand Internet connectivity in the country.

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...(Interruptions)... One minute. Your question is over. Shrimati Kahkashan Perween.

Q.No. 21(CONTD.)

श्रीमती कहकशां परवीनः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि पिछले पांच सालों में गांवों में बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है या घटी है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि इन दो सालों में कितने गांवों में स्पीड हाई-फाई नेटवर्क लगाए गए हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, इस विभाग को अब मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ और यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज कल बीएसएनएल 20 लाख कस्टमर्स प्रति महीने ऐड कर रहा है और वह इस क्षेत्र में देश में चौथे नंबर पर आ गया है, जब कि पहले इनकी संख्या 5 या 6 लाख में हुआ करती थी। इस विकास के लिए उनका सम्मान तो होना चाहिए और वह गांवों में भी बहुत काम कर रहा है। सभापति जी, चूंकि माननीय सदस्या ने स्पेसिफिक संख्या मांगी है, इसलिए मैं विभाग को कहूंगा और वहां से लेकर हम उनको प्रोवाइड करा देंगे।

एक बात हमें अवश्य कहनी चाहिए, वह यह है कि भारत में जो तकनीकी बदलाव हो रहा है, उसके मद्देनजर मैं देख रहा हूँ कि विस्तार से नई-नई सेवाएं शुरू होंगी और बीएसएनएल भी उनको काफी इम्प्रूव करेगा, एमटीएनएल दिल्ली में लगभग हजार नए बीटीएस लगाने की योजना बना रहा है, मुम्बई में वह काफी काम कर रहा है।

Q.No. 21(CONTD.)

इस प्रकार से हम मिल कर काम करेंगे, निजी क्षेत्र भी काम करेंगे और पीएसयूज़ भी काम करेंगे। ऐसे मिल कर देश को सशक्त करेंगे।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No. 22.

Q. No. 22

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, this is a very important question that needs to be dealt with at length, but, this being the Question Hour, I would like to make it concise. I would request you to permit a separate discussion on this subject.

Sir, India is basically an agricultural country and our population is increasing enormously.

(CONTD. BY RSS/1Z)

RSS/NKR/1Z/12.55

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): And sooner or leter, we are going to surpass even China in population, whereas, the area of India is only one-third of China. In this situation, when the requirement for food is increasing, the cultivable agricultural lands are being converted for non-agricultural purposes. Sir, the statistics show very clearly that in the year 2013-14, 26.91 million hectares of agricultural land have been converted for non-agricultural purposes, that is, 2 crore 70 lakh hectares of agricultural land. When the population is increasing and when the food requirement is increasing, it is diminishing or decreasing to this very, very alarming situation, what are the

Q.NO. 22 (CONTD.)

steps the Government is keeping in mind? They may say that it is a State issue, but, when the Central Government can issue directions to the State Government how to acquire lands and all, there must be a stringent law that agricultural lands should not be converted for non-agricultural purposes. I would like to know whether the Ministry is having such an intention.

श्री परषोत्तम रुपाला : चेयरमैन सर, माननीय सांसद श्री तिरुची शिवा ने जो प्रश्न उठाया है कि एग्रीकल्चरल जमीन घट रही है और फूड सिक्योरिटी के बारे में चिंता जताई है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर आप तथ्यों पर गौर करें, 2010 से लेकर वर्तमान समय तक एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो टोटल प्रोडक्शन की फिगर्स हैं, उनके अनुसार पहले 244 मिलियन टन से बढ़ कर, इस साल, अभी तक वर्ष 2015-16 की जो फिगर्स हैं और आने वाले वर्ष 2016-17 की फिगर्स हैं, हम 252 मिलियन टन तक पहुंचे हैं। इसी तरह अगर कन्टीन्यूटी में आप देखें, तो वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में, जब सूखे का समय था, उस समय भी देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन तो घट रही है, यह फैक्ट है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन विकास के जितने काम हो रहे हैं, नई सड़कें बनेंगी, नई रेल लाइनें बनेंगी, नए रास्ते बनेंगे, नई आबादी के लिए घर बनेंगे, उसके लिए जमीन तो कटेगी, मगर इसके इलाज के लिए, खासकर माननीय सांसद ने जैसा अभी बताया कि हमारी आबादी बढ़

Q.NO. 22 (CONTD.)

रही हैं और हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे, उन्हें खाने की दिक्कत न हो, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत न हो, इसके लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके अंतर्गत इस साल में आज तक इतिहास का रिकॉर्ड उत्पादन इस देश का किसान करने जा रहा है, यह मैं आपके माध्यम से संसद के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Minister's reply is justifying that the conversion of cultivable agricultural lands to non agricultural lands will not affect the food production. Sir, I would like to know from the hon. Minister one thing. When he says that food production has increased comparatively what it was, and what it is now, and whether it would meet the demand and supply situation. Agricultural sector is the largest sector which provides more employment, and production which he says nowadays is by way of modern technology. Non-conventional methods do not suit our soil, and it has already displaced too many numbers of agricultural workers, and introduction of genetically modified seeds would also encourage the farmers that they would get more yield. But, in that case, we have to stretch our hands to foreign countries even for our seeds, and our conventional agriculture would be totally erased. So, in that situation, statistics showing that food production has increased by non-conventional methods, will not suit us. We have to stick on to

Q.NO. 22 (CONTD.)

conventional methods. What I would urge the Minister is that kindly see to that no more agricultural land is converted for non-agricultural purpose.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

(followed by 2a/KGG)

KGG-DS/2A/1.00

श्री परषोत्तम रुपाला : माननीय सभापति जी, मेरा कहना यह कतई नहीं था कि agricultural land का non-agricultural land में जो conversion हो रहा है, उससे हमें खुशी हो रही है या हम इसके पक्ष में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार यह चाहती ही नहीं है कि agricultural land का non-agricultural land में conversion हो।

MR. CHAIRMAN: I am afraid, Question Hour is over. The House is adjourned till 2.30 p.m.

--

The House then adjourned for lunch at one of the clock.